जल संरक्षण के नाम पर बढ़ता गया बजट, घटता गया जलस्तर

विभागीय अमले की होती रहीं जेबें गरम

नवभारत न्यूज

पन्ना, 9 अप्रेल। जल संरक्षण के नाम पर बहुत प्रयास हुए किंतु उसके परिणाम सकारात्मक नहीं आये पाये। उद्देश्य था कि घटते जल स्तर को बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किये जाय। इसलिए इसको लेकर योजनाएं और परियोजनाएं को स्वीकृति भी मिली। पंचवर्षीय योजनाएं के तहत उनका क्रियान्वयन भी किया गया। किंतु आज यदि देखा जाय तो पता चलता है कि जल स्तर नहीं बढ़ चुका। जिसका परिणाम समय से पहले तेजी से घटते जल स्तर के रूप में सामने आ रहा है।

जल स्तर भले ही नहीं बढ़ा सिर्फ शासकीय बजट बढ़ा देने से सम्बंधित विभागीय अमले की जेबें अवश्य गरम हो गई और उनकी अवैध कमाई में अवश्य बढ़ोत्तरी हुई है।

निर्मित संरचनायें आंकड़ों तक- जल संरक्षण के नाम पर निर्मित होने वाली संरचनाओं का डाटा पता किया जाय तो पता चलेगा कि जब से इस विषय में चिंता हुई और प्रोजेक्ट शुरू हुए तब से आज तक व्यापक पैमाने पर संरचनाओं को निर्माण किया गया। पुराने अभिलेखों में ऐसे प्रमाण आज भी मिल सकते हैं। किंतु उन संरचनाओं की आज यदि खोजबीन होगी एवं उनका भौतिक सत्यापन होगा तो दस फीसदी संरचनाएं भी भौतिक रूप से नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति मे इसका जबाव कौन देगा कि निर्मित होने वाली संरचनाएं यदि बनी तो वे कहां विलुप्त हो गई। आखिर कुछ न कुछ अंश तो दिखना चाहिए। कुछ न कुछ प्रमाण तो मिलना ही चाहिए। किंतु यहां धरातल में कुछ भी नहीं मिल सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां न तो नहरें और न ही कोई बांध वहां यह समस्या और भी कठिन होती है। चूंकि ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल ही एक माध्यम होता है जिसके सहारे खेती भी होती है और उद्यानिगकी से लेकर अन्य दैनिक उपयोग में प्रयोग होता है। आज वही स्थिति दिखाई दे रही है। आज यह सवाल भी रहे हैं कि आखिर इतने वर्षो से जल संरक्षण के नाम पर भारी भरकम राशि खर्च हुई, किंतु उसका परिणाम क्या निकला। सकरात्मक परिणाम आखिर क्यों नहीं निकल पाया। जल स्तर क्यों नही बढ़ा। तकनीकी रूप से जो अध्ययन किये गये थे और जो दिशा निर्देशों दिये गये थे उसी के अनुसार यदि योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ तो कुछ परिणाम तो दिखने चाहिए। किंतु यहां तो स्थिति और भी भयावह ही दिखाई दे रही है।

पुरानी जल संरचनायें भी विलुप्त

पुरानी जल संरचनाओं को भी सुनियोजित साजिस के तहत नष्ट कर दिया। आज मनरेगा से कपिलधारा कूप के नाम पर कुंओं का निर्माण करवाया जा रहा है। किंतु इसके विपरीत कई पुराने कुएं व बावडियों को नष्ट कर दिया गया या नष्ट किया जा रहा है। जबकि ऐसी पुरानी संरचनाओं को पुनर्जीवित किया जा सकता था। इसी तरह से कई तालाबों को भी नष्ट कर दिया गया। वहां खेती शुरू हो गई। अथवा शहरी क्षेत्र में होने के कारण वहां कॉलोनियों का निर्माण हो गया, आबादी क्षेत्र बन गये, आवासीय कॉलोनियों का निर्माण हो गया। आज ऐसे क्षेत्रों में उन तालाबों के नाम पर मुहल्ले जरूर बस चुके हैं। इसी तरह से जो शेष बचे हुए हैं, उनका भी अस्तित्व संकट में हैं क्योंकि यहां पुनरूद्धार के नाम पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। अन्यथा कई तालाबों को जिंदा किया जा सकता है।

एनसीईआरटी की तुलना में पांच गुना ज्यादा रेट पर मिल रहीं किताबें

अभिभावक खुलेआम लुटने को मजबूर

नवभारत न्यूज

पन्ना, 9 अप्रेल। अप्रैल माह से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। पन्ना जिला मुख्यालय पर इस वर्ष पुस्तक मेला का आयोजन नहीं किया गया। इसके अलावा शहर सहित जिले में निजी स्कूलों द्वारा महंगी किताबें अनिवार्य किए जाने का मामला सामने आया है। जहां एक ओर एनसीईआरटी की किताबें बेहद सस्ती हैं, वहीं निजी प्रकाशकों की किताबें 5 से 10 गुना अधिक कीमत पर अभिभावकों को खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

जिला प्रशासन भले ही पुस्तकें, ड्रेस और फीस को लेकर पारदर्शिता की बात की जा रही हो, पर जमीनी हकीकत में इसका सब उलट है। वहीं अभिभावकों ने बताया कि कक्षा पहली की हिंदी विषय की एनसीईआरटी किताब की कीमत मात्र 65 रुपए के आसपास है। जबकि उसी विषय की निजी प्रकाशक की किताब 250 से 400 तक में बेची जा रही है। यही नहीं, कई स्कूलों में एक ही विषय की दो-दो किताबें अनिवार्य कर दी गई हैं, जिससे अभिभावकों का खर्च और बढ़ गया है। आनंद कुमार, एनके दुबे ने बताया कि कक्षा पहली का 1500 से 2 हजार और इसके आगे की कक्षा का कोर्स और महंगा दिया जा रहा है। कक्षा 10वीं तक का कोर्स 5 से 7 हजार तक में मिल रहा है। इस वर्ष निजी स्कूलों द्वारा मनमाने प्रकाशक से पुस्तकें संबंधित स्टेशनरी दुकानों पर कक्षावार कोर्स रखवाया गया है। शिक्षा के नाम पर बढ़ते इस व्यावसायिक दबाव ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन द्वारा समय रहते सख्ती नहीं की गई, इसलिए यह समस्या बढ़ गई है। आने वाले समय में और चिंताजनक हो सकती है। स्कूलों की स्टेशनरी तय, वहीं से खरीदने का दबाव- अभिभावकों का आरोप है कि निजी स्कूलों ने कुछ चुनिंदा स्टेशनरी दुकानों से साठगांठ कर रखी है। किताबें सिर्फ उन्हीं दुकानों पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे अभिभावकों के पास विकल्प नहीं बचता। शहर के कुछ नामी स्कूल प्रबंधन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वहीं से किताबें खरीदने का दबाव बनाया जाता है। शहर में पड़ताल में सामने आया कि एनसीईआरटी की 65 रुपए की किताब मिल रही है, इसके अलावा वहीं पुस्तक निजी प्रकाशक करीब 300 रुपए तक की कीमत रखी गई।

हर साल बदलता कोर्स, पुन : उपयोग संभव नहीं

निजी स्कूलों में हर साल किताबें बदलने का चलन भी अभिभावकों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। इससे पुरानी किताबों (कोर्स) का उपयोग नहीं हो पाता और हर वर्ष नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं। इसमें जिला प्रशासन द्वारा भी सिर्फ वातानुकूल कमरों में बैठकर रूपरेखा तो बनाई जाती है, पर जमीनी हकीकत इसके उलट रहती है। जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी निजी स्कूल को हर साल बदलने वाली पुस्तक के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। हर बार पुस्तकें बदलने से साठगांठ को भी बल मिलता है।

मूलभूत सुविधाओं को मोहताज अवैध कॉलोनियों के निवासी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 9 अप्रेल। जिला मुख्यालय के आसपास भू माफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही है और लम्बी चैड़ी सुविधाओं को वादा कर प्लॉट बेंच देते हैं और फिर मकान बनाकर रहने वाले रहवासियों को सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलता है और वे अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं।

ज्ञात हो कि जिले भर में अवैध कॉलोनियों का जाल फैलता जा रहा है। भू माफिया लोगों को बेहतर कॉलोनी का सपना दिखाकर ठग रहे हैं, इनके शिकार लोग वर्षो से वादों को पूरा होने की उम्मीद में बैठे परेशान हैं ऐसे लोगों की न तो प्रशासन को परवाह है और न ही अवैध प्लाटिंग करने वाले कथित कॉलोनाइजरों को। जिसके चलते आज अपनी जमापूंजी लगाकर घर बनाने वाले लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। पन्ना शहर व आसपास के ग्रामीण अंचलों में बनी ऐसी दर्जनों कॉलोनियां हैं, जहां लोगों ने अपने आशियाने बनांए हैं। लेकिन यहां न तो आज तक लोगों को पक्की सड़क मिली, न ही गंदे पानी की निकासी का यहां कोई प्रबंधन है। न तो कॉलोनी में पानी की टंकी है और न ही नल जल की सुविधा। लोगों को प्लाटिंग करने वाले लोगों ने खूब सपने दिखाए थे, बताया था कि जल्दं ही कॉलोनी नगर पालिका में शामिल हो जायेगी और पूरी सुविधाएं मिलेंगे। प्लाटिंग के दौरान कच्ची सड़क बना कर इन्हें दे दी गई। कुछ स्थानों पर रसूखदार लोगों द्वारा नगर पालिका से पहुंच के बल पर सड़क तो बनवा ली, लेकिन अन्य सुविधाओं के लिए यहां के रहवासी आज भी परेशान हैं।

चल रहा अवैध कालोनियों का कारोबार

नगर पालिका क्षेत्र सहित शहर से लगे ग्रामों पुरूषोत्तमपुर, पुराना पन्ना, जनकपुर, गांधी ग्राम, टपरियान, गहरा, कुंजवन आदि में अवैध प्लाटिंग का खेल आज भी चल रहा है। जहां रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी(रेरा) नगर एवं ग्राम निषेध व मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनाइजर एक्ट 1998 के नियमों को दरकिनार का प्लाट बेंच रहे हैं। इसके चलते प्लाट खरीदने वाले लोग भविष्य में वैसी परेशानी में फंस सकते जैसा की पूर्व में बनी कॉलोनियों में लोग झेल रहे हैं। बताया जाता है कि बिना शहर एवं ग्राम निवेश से नक्शा अनुमोदित इन कॉलोनियों में कॉलोनाइजर नियमों का पालन नहीं किया गया है। जिसके चलते इन कॉलोनियों को नगर पालिका में मर्ज नहीं किया जा सकता। इन अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बारिश के दिनों विशेष रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है सड़क नहीं होने के कारण कीचड़ में सन कर घर पहुंचना होता है।

भू माफियाओं का दबदबा

अवैध प्लाटिंग के कारोबार में जुडे रसूखदार भू माफियाओं की ऊंची पहुंच के चलते आज तक प्रशासन ने इन पर अंकुश लगाने का प्रयास तक नहीं किया। कुछ एक मामलों में व्यक्तिगत शिकायत के बाद कार्यवाही जरूरत देखी गई। आलम यह है कि रसूखदार भू माफियाओं के आगे आम आदमी ठगों के बाद भी शिकायत तो दूर बात करने तक से घबराता है। पन्ना शहर की बात करें तो यहां आसपास के ग्रामीण अंचलों में कृषि की भूमि को डायवर्ट कराकर बिना कॉलोनाइजर पंजीयन बेचने का कारोबार लगातार जारी है। पुरूषोत्तमपुर जेल के पास बाउण्डरी से लगकर प्लाटिंग हो रही है। जहां लोगों को सुविधा युक्त प्लाट व बेहतर कॉलोनी के नाम पर ठगा जा रहा है। दिखावे के लिए अन्य जिलों के कॉलोनाइजर पंजीयन वाली फर्मो को प्लाटिंग में पार्टनर बनाकर उपयोग किया जा रहा है। जबकि प्लाट की रजिस्ट्री व्यक्तिगत रूप से की जा रही है, कॉलोनाइजर पंजीयन मात्र दिखावा है।

देवेंद्रनगर पुलिस ने 72 घंटे में खोजा पूर्व विधायक का मोबाइल

नवभारत न्यूज

पन्ना, 9 अप्रेल। तकनीक जब तत्परता से मिलती है, तो परिणाम सुखद होते हैं। थाना प्रभारी देवेंद्रनगर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी कौशल का परिचय देते हुए पूर्व विधायक शिवदयाल बागरी का गुम हुआ मोबाइल महज 3 दिनों के भीतर बरामद कर लिया।

इस सफलता में भारत सरकार के सीईआईआर पोर्टल ने अहम भूमिका निभाई। मोबाइल वापस मिलने पर पूर्व विधायक ने पुलिस की कार्यप्रणाली को सराहनीय

बताते हुए कहा कि यह सफलता पुलिस पर जनता के बढ़ते भरोसे का प्रतीक है।

मड़ला घाटी में लगभग हर दिन लग रहा जाम, यात्री परेशान

नवभारत न्यूज

पन्ना, 9 अप्रेल। पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पड़ने वाली मंडला घाटी विगत कुछ महिनों से लगातार हर दिन जाम के लिये जानी जा रही है, जिससे जहां यात्री गन्तव्य तक नहीं पहुंच पाते वहीं वन्य प्राणियों का खतरा भी हमेशा बना रहता है।

पन्ना आने वाले पर्यटकों और यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को हो रही है जो खजुराहो रेलवे स्टेशन के लिए इस मार्ग का उपयोग करते हैं। जाम के कारण कई बार यात्रियों की ट्रेन तक छूट जाती है। स्थिति यह है कि इस मार्ग पर कब और कितनी देर का जाम लग जाए, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। भैरव टेक और मड़ला घाटी के खतरनाक मोड़ों पर सड़क की खराब हालत जाम का प्रमुख कारण बन रही है। जगह-जगह गड्ढे, टूटी सुरक्षा दीवारें और खराब रोड शोल्डर के चलते वाहन चालकों को क्रॉसिंग में भारी दिक्कत होती है। खासकर बड़े वाहनों के फंसने से लंबा जाम लग जाता है। समय-समय पर सड़क चैड़ीकरण और सुधार की बातें होती रही हैं, लेकिन धरातल पर अब तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। यहां तक कि नियमित मरम्मत भी नहीं कराई जा रही है।

यह मार्ग पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिससे जाम की स्थिति वन्यजीवों के लिए भी खतरा बन गई है। जाम के दौरान वाहनों की लंबी कतारें और शोर-शराबा वन्यजीवों के प्राकृतिक व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर बृजेन्द्र श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुधार या निर्माण कार्य को लेकर पार्क प्रबंधन को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के कई संरक्षित क्षेत्रों से सड़कें गुजरती हैं और उनका नियमित रखरखाव भी होता है। यदि विभाग से अनुमति मांगी जाती है तो तत्काल दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि जाम के कारण कई बार वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी प्रभावित होते हैं, जिससे कार्य में बाधा आती है।

गर्मी में बेल का शरबत सेहत के लिए सर्वाधिक फायदेमंद

नवभारत न्यूज

पन्ना, 9 अप्रेल। प्राचीन काल में बेल फल की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए इसे श्रीफल की संज्ञा भी दी गई थी। जिले के जंगलों में बेल के वृक्ष प्राकृतिक के रूप में बहुतायात से पाये जाते हैं।

इस वृक्ष की सबसे बडी विशेषता यह है कि इसे हर तरह की बंजर भूमि यथा ऊसर, बीहड, खादर, शुष्क एवं अर्द्धशुष्क में भी लगाया जा सकता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी से लेकर खनिज तत्व और और कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा पायी जाती है। औषधि गुणों से भरपूर

होने के कारण घरों में इसका शरबत और मुरब्बा बनाकर रखा जाता है। बेल का फल अप्रैल से पकना शुरू होता है तो जून तक पके फल मिलते रहते हैं इसके पके फल ही उपयोग में लाए जाते हैं। बेल का डंठल इतना मजबूत होता है कि पक कर भी भी लम्बे समय तक फल पेड में ही लगा रहता है, लेकिन जून में सभी पके फल झड़ जाते हैं और सूखने के बाद बरसात में फल के अंदर बीज जम कर आवरण के बाहर आकर जमीन में उग जाता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने सभी प्रकृति प्रदत्त भोजन को अपना बना लिया है। अप्रैल से शरबत पीना शुरू करना है तो जून तक चलता रहता है। बेल फल का हांथियों का पसंदीदा भोजन है। इसलिए इसका नाम हांथी एप्पल एवं चूंकि खोल हार्ड लकडी का बना होता है इसलिए इसे लकडी सेव भी कहते हैं गर्मी के मौसम में प्रकृति प्रदत्त इस तोहफे बेल के फल में विटामिन और पोषक तत्वों की भरमार होती है बेल के मौजूद टेनिन और पेक्टिन मुख्य रूप से डायरिया ओर पेचिश के इलाज में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा बेल के फल में विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन और आयरन भी अधिक मात्रा में मिलते हैं। बेल के नियमित सेवन से शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढती है।

पेट्रोल पम्प के मैनेजर पर 7 लाख 88 हजार रुपए के गबन का आरोप

संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज, आरोपी फरार

नवभारत न्यूज

पन्ना, 9 अप्रेल। शहर के सिविल लाइन स्थित पन्ना फिलिंग स्टेशन में नियुक्त मैनेजर पर क्रय-विक्रय से प्राप्त राशि के हिसाब में हेराफेरी कर 7 लाख 88 हजार रुपए की राशि गबन कर लापता हो जाने के आरोप लगे है।

मामले को लेकर पेट्रोल पम्प के संचालक राजेश कुमार द्विवेदी पिता स्वर्गीय जग प्रसाद द्विवेदी 56 वर्ष निवासी वार्ड 13 छत्रसाल वार्ड बेनीसागर मोहल्ला की लिखित शिकायत पर कोतवाली पन्ना में आरोपी रामकेश पटेल पिता राजा भइया पटेल निवासी लोढ़ापुरवा तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना के विरुद्ध बीएनएस की धारा 316(4) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। फरियादी राजेश द्विवेदी ने लिखित आवेदन में बताया कि उनका पन्ना फिलिंग स्टेशन के नाम से सिविल लाइन में पेट्रोल पम्प 2015 से संचालित है जो कि अनुजबधु साधना द्विवेदी के नाम दर्ज है। फिलिंग स्टेशन पर आरोपी रामकेश पटेल को प्रबंधक पद हेतु नियुक्त किया गया था। वह पेट्रोल डीजल व आयल की खरीद-बिक्री, हिसाब किताब का जिम्मेदार था। 26 फरवरी को रामकेश बिना सूचना के चला गया। 27 फरवरी को जब वह कार्य स्थल पेट्रोल पम्प नहीं आया तो उसके घर व उसके फोन पर सम्पर्क किया लेकिन फोन बंद था और धाम मोहल्ला में जिस जगह वह वर्तमान में रहता था वह खाली मिला। 3-4 दिनों के इंतजार के बाद शंका होने पर पेट्रोल पम्प के हिसाब किताब की जांच की तो 7 लाख 88 हजार 250 रुपए का हिसाब नहीं मिला जो कि आरोपी गबन करके लापता हो गया है।

सिमरा कलां के मंदिर से घंटे चोरी करने वाले दो शातिर अपराधी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

पवई 9 अप्रैल। पन्ना पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा एवं संपत्ति संबंधी अपराधों में खुलासा करने हेतु निर्देशित किया गया।

जिस पर बीते दिवस थाना पवई में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि ग्राम सिमरा कला के प्राचीन मसान बब्बा मंदिर से श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाये गये पूजा के घंटे कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया है जिस पर थाना पवई में अपराध क्रमांक 115/26 धारा 331(4) ,305(क) की धारा में प्रकरण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती वंदना सिंह , अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमती

भावना दांगी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुशील कुमार के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई जिसने मुखविर की सूचना के आधार पर दो आरोपियों के कब्जे से उक्त चोरी हुये समस्त 29 नग मंदिर के घंटे जिसकी कीमती करीबन 70,000 हजार रुपए के साथ मोटरसाइकिल को जप्त किया। अग्रिम कार्यवाही जारी है। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी पवई सुशील कुमार ,सहायक उप निरीक्षक रामसजीवन तिवारी ,आरक्षक राहुल अहिरवार, आरक्षक रमाकांत कुर्मी ,वाहन चालक नागेन्द्र मांझी की भूमिका रही ।

परीक्षाओं में उड़नदस्ता कर रहा है निरन्तर दौरा

नवभारत न्यूज

पन्ना, 9 अप्रेल। आज 9 अप्रैल को जिला स्तरीय उड़नदस्ता ने पन्ना जिले की महाविद्यालयों में चल रही विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं का औचक निरीक्षण किया।

जिला स्तरीय उड़नदस्ता के संयोजक डॉ एस डी चतुर्वेदी, अन्य सदस्य वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ जे.के. वर्मा, डॉ पूनम सिंह एवं सिद्धू सिंह सहायक प्राध्यापक संयुक्त रूप से सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना में चल रही प्रथम पाली पूर्वाह्न 9 से 12 बजे की परीक्षा का निरीक्षण किया गया, जिसमें कोई भी नकल प्रकरण नहीं बनाया गया। द्वितीय पाली अपराह्न 02 से 5 बजे की परीक्षा में शासकीय महाविद्यालय अमानगंज का औचक निरीक्षण के उपरांत एक नकल प्रकरण बनाया गया एवं शासकीय महाविद्यालय पवई में कोई भी नकल प्रकरण नहीं बनाया गया। जिले की महाविद्यालयों में परीक्षा संबंधित व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से पाई गई।

लगभग 11 करोड़ की लागत से बनेंगे पवई शाहनगर के नवीन जनपद पंचायत भवन, हुआ भूमिपूजन

नवभारत न्यूज

पवई 9 अप्रैल। जनपद पंचायत पवई के नवीन भवन के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 525.67 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बुधवार को पवई विधायक प्रहलाद लोधी के मुख्य आतिथ्य और जनपद अध्यक्ष श्रीमती मोहनी आनंद मिश्रा के विशिष्ट आतिथ्य में भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ।

भूमि पूजन पूर्व विधि विधान के साथ शिलालेख को लगाया गया पूजा की गई। इस दौरान पवई विधायक और जनपद अध्यक्ष के द्वारा डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों का उल्लेख किया और उनकी सरकार के द्वारा पवई के विकास के लिए लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य किया जा रहे है। उन्होंने आगे भी पवई क्षेत्र के विकास के लिए इसी तरह विकास कार्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। बता दें कि शाहनगर में भी 525.67 लाख की लागत से भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी पवई अखिलेश उपाध्याय को शाहनगर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस अवसर पर आर ई एस विभाग के मुख्य कार्यपालक यंत्री बी के रिछारिया, एसडीएम समीक्षा जैन, जनपद उपाध्यक्ष सुखदेव सिंह, जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि सचिव, रोजगार सहायक व पत्रकार साथी मौजूद रहे।

आरटीओ कार्यालय में सुविधा शुल्क में नहीं लग रहा अंकुश, प्रायवेट कर्मचारी बने वसूलीकर्ता

नवभारत न्यूज

पन्ना, 9 अप्रेल। लम्बे समय से सुविधा शुल्क के लिए चर्चित आरटीओ कार्यालय एक बार फिर अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक ओर जहां जिला परिवहन अधिकारी अपने आपको ईमानदार बताने में कोई कोताही नहीं बरतते। वहीं दूसरी ओर उनके नाक के नीचे मातहत की ईमानदारी पर बट्टा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

अहम बात तो यह है कि जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में चल रहे सुविधा शुल्क के इस खेल में साहब की चुप्पी उनकी मूकसहमति साबित हो रही है तथा मातहतों द्वारा इस चुप्पी का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। चर्चा तो यहां तक है कि वर्तमान समय में कार्यालय के लिपिक से लेकर अनाधिक्रत तौर पर रखे गए प्राइवेट कर्मचारी भी इस वसूली अभियान में भरपूर सहयोग कर रहे हैं। चर्चा तो यहां तक है कि नजराने के बिना ट्रायल के ही जारी हो रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। जबकि नजराना न देने वालों से मांगा जाता है गाड़ी का पेपर एवं अपनी ही गाड़ी लाकर ट्रायल कराया जाता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रतिदिन दर्जनों लाइसेंस जारी होते हैं। लेकिन आज तक किसी भी लाइसेंस धारी से ट्रायल कराते नहीं देखा गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में प्रतिदिन लाइसेंस लेने वालों की कतार देखी जा सकती है। लेकिन इस कार्य की जिम्मेदारी उठाने वालों

की सांठगांठ के चलते अतिरिक्त नजराना जमा करने वालों को न तो ट्रायल देने की जरूरत पड़ती है और न ही वाहन की आरसी ही मांगी जाती है। लेकिन यदि लाइसेंस की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति द्वारा डायरेक्ट लाइसेंस का आवेदन दिया जाता है तो उसे अपनी गाड़ी एवं गाड़ी का पेपर लाकर अपने ही वाहन से ट्रायल देने की बात इस जिम्मेदारी को सम्भाल रहे लिपिक द्वारा की जाती है।

वर्तमान समय में जिला परिवहन कार्यालय में सुविधा शुल्क का किस हद तक बोलबाला है इस बात का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि यदि किसी भी आवेदक का मोबाईल जो ड्राइविंग लाइसेंस में जुड़ा है, गुम जाता है या आवेदक का मोबाईल नम्बर बदल जाता है तो वर्तमान नम्बर अपडेट कराने के लिए भी सुविधा शुल्क अनिवार्य है। बिना सुविधा शुल्क के यह काम भी संभव नहीं है।

लोगों को यह बात आज तक हजम नहीं हो सकी कि एक कर्तव्य निष्ठ अधिकारी का दंभ भरने वाने आरटीओ के नाक के नीचे बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं होता और जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में मौन हैं। किसी प्रकार की कार्यवाही न होने से मातहतों का मनोबल ऊंचा है तथा वह बेखौफ होकर नजराना वसूल रहे हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार जिला परिवहन कार्यालय में जहां विभागीय कर्मचारी अलग-अलग कार्यों के लिए निर्धारित सुविधा शुल्क की वसूली खुलेआम कर रहे हैं तथा उनके द्वारा बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं किया जाता। वहीं दूसरी ओर संबंधित कर्मचारियों से प्राप्त सुविधा शुल्क की वसूली एवं एकत्रिकरण के लिए एक प्राइवेट डीलर की मौखिक तैनाती जिला परिवहन कार्यालय में किया जाना चर्चा का कारण बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार जिला परिवहन कार्यालय में एक प्राइवेट डीलर की मौखिक नियुक्ति की गई है। जो विभिन्न कार्यों के लिए नियुक्त कर्मचारियों से नजराने की राशि एकत्रिकरण का कार्य करते हैं। संबंधित कार्यों के लिए नियुक्त अलग-अलग प्रायवेट कर्मचारी दिन भर की सुविधा शुल्क की वसूली की प्राप्त राशि पहुंचाते हैं। बाद में उक्त डीलर द्वारा कहां पहुंचाया जाता है यह आज तक अबूझ पहेली बना हुआ है।